21 © DECEMBER SATURDAY 2019

355-010 WEEK 51

Name - Raj Kapoor verma

college name - Shakuntalam Institute of Teachers education At - Kri hindi Kumhu station sasaram

Class - B-Ed , 1st year

paper - C-2 - समकालीन भारत एवं शिक्षा

unit - 2

# भारतीय शिक्षा आयोग -1882
# (हण्टर कमीशन)

## आयोग की नियुक्ति के कारण :

1854 के वुड के आज्ञापत्र ने भारत में शिक्षा का प्रसार करने का उत्तरदायित्व कम्पनी पर सुनिश्चित किया था और निस्यंदन सिद्धांत की आलोचना की थी परन्तु सरकार इस संस्तुती को न मानते हुए अधिक धन माध्यमिक विद्यालय, कॉलेजों और विश्वविद्यालय कि स्थापना में ही व्यय करती रही जिससे प्राथमिक शिक्षा का विकास नहीं हो सका था। देशी विद्यालयों की उपेक्षा के कारण जनता में असंतोष था।

## उद्देश्य

1. शिक्षा जीवन के व्यवहारिक पक्ष से जुडी हुई हो।
2. जन शिक्षा प्रसार

## * आयोग की नियुक्ति *

3 फरवरी 1882 ई० को गवर्नर जनरल लार्ड रिपन ने भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की इस आयोग के अध्यक्ष प्र० विलियम विल्सन हण्टर बनाए गए थे। इसलिए इसे हण्टर आयोग कहा जाता है। इस आयोग के सचिव बी० एल० राइस थे। इसमें 20 सदस्य थे जिसमें 7 भारतीय सदस्य थे।

### आयोग का प्रतिवेदन

आयोग ने समस्त भारत देश का भ्रमण करके 7 सप्ताह कलकत्ता और 7 महीने में भारत के विभिन्न प्रान्तों में लोगों से मिलकर तथ्य एवं सूचनाएँ संकलित की जिनमें प्रान्तीय सरकारों के प्रतिवेदन (Report) भी थे। अपने सुझावों एवं संस्तुतियों का 600 पृष्ठों का प्रतिवेदन तैयार करके मार्च 1883 ई० को सरकार के सामने प्रस्तुत किया था

### आयोग का कार्य-क्षेत्र

1. 1854 के नीति का किस सीमा तक पालन हुआ।
2. भारत में प्राइमरी शिक्षा की क्या स्थिति है
3. सरकारी विद्यालय और व्यक्तिगत प्रयास की शिक्षा में क्या भूमिका है

AUGUST
M T W T F S S M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
26 27 28 29 30 31

## प्राथमिक शिक्षा

**नीति**

1. प्राथमिक शिक्षा, जन साधारण की शिक्षा के रूप में मानी जाए।
2. पिछड़े जिले में उदार सहायता अनुदान देकर प्राथमिक शिक्षा का विस्तार किया जाना चाहिए।

**भाषा** — देशी भाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाए।

**प्रशासन** — (1) भारत में प्राथमिक शिक्षा के विधान और प्रशासन के लिए आयोग ने ब्रिटेन की कांउन्टी काउन्सिल (county council) को आदर्श मानकर प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व county council को सौंप दिया गया था। इसी आधार पर भारत में भी आयोग ने ग्रामीण क्षेत्रों में जिला परिषदों तथा नगर क्षेत्रों में नगरपालिकाओं की स्थापना के लिए सुझाव दिया। प्राथमिक शिक्षा का समस्त उत्तरदायित्व इन्हीं स्थानी निकायों को सौंपना का सुझाव दिया

(2) जिन जिला परिषदों और नगरपालिकाओं की स्थापना हो वे स्कूल जिले मान लिए जाए। इन स्कूल जिलों में स्कूल परिषदों के उत्तरदायित्व में अनेक उनके अधीन क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय का प्रचार एवं प्रसार होना चाहिए।

SEPTEMBER
M T W T F S S M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29 30

(3) प्रत्येक प्रान्त में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए।

## विद्यालय प्रशासन

(1) पाठ्यक्रम प्रांत अपनी आवश्यकता के अनुसार तय करेगा।

(2) व्यावहारिक अंकगणित की भारतीय विधियाँ और बहीखाता जैसे व्यवहारिक विषय प्रारम्भ होने चाहिए।

(3) विज्ञान, गणित, प्राकृतिक विज्ञान पाठ्यक्रम में होने चाहिए।

(4) कताई बुनाई एवं घरेलू संबंधी कार्य में शिक्षा का माध्यम लोकल भाषा होगी।

(5) परीक्षा विद्यालय निरीक्षकों द्वारा ली जानी चाहिए।

## ✱ माध्यमिक शिक्षा ✱

सरकार का कर्तव्य प्रत्येक जिले में केवल एक हाईस्कूल की स्थापना करना है इसके पश्चात माध्यमिक शिक्षा का प्रसार व्यक्तिगत प्रयासों पर छोड़ देना चाहिए।

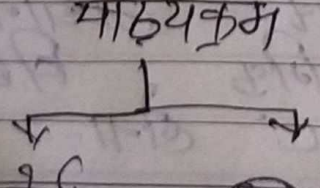

माध्यम :— अंग्रेजी

पाठ्यक्रम —

पाठ्यक्रम

(अ) कोर्स (ब) कोर्स

6



अ - कोर्स - साहित्यिक (जो विश्व विद्यालय में प्रवेश लेना चाहते हो)

ब - कोर्स - व्यावहारिक (व्यावसायिक)

* शिक्षा के अन्य पक्ष *

शिक्षक प्रशिक्षण

1. नार्मल स्कूलों की स्थापना हो चाहे वह राजकीय हो या सहायता प्राप्त।

2. एक प्रान्त में एक ही नार्मल स्कूल होने चाहिए।

3. इनमें मनोवैज्ञानिक स्तर पर पाठ्यक्रम विकसित करना, प्रैक्टिकल पर आधारित शिक्षा देना न की थ्यूरी (Theory) बेस पर।

4. प्रत्येक विद्यालय निरीक्षक के क्षेत्र में एक ट्रेनिंग institute होनी चाहिए।

वित्त

प्राथमिक शिक्षा को लोक शिक्षा की सम्पूर्ण व्यवस्था का वह भाग घोषित कर देना चाहिए जो शिक्षा के लिए पृथक रखे गए स्थानीय कोष पर प्रायः एकमात्र अधिकार और प्रान्तीय आय पर वृहत्त

अधिकार रखती है।"
प्राथमिक शिक्षा के लिए विशेष कोष तैयार होना चाहिए।

धार्मिक शिक्षा

1. राजकीय विद्यालय में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा न दी जाए।
2. गैर सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा प्रदान की जा सकती है।

मुस्लिम शिक्षा

1. मुस्लिम शिक्षा को विशेष प्रोत्साहन देने का भार स्थानीय संस्थाओं एवं प्रान्तों पर होना चाहिए।
2. मुस्लिम प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षण स्तर को ऊँचा उठाया जाना चाहिए।
3. छात्रवृत्तियाँ अधिक दी जाए, आर्थिक सहायता प्रदान की जाए।
4. प्राथमिक विद्यालय में निरीक्षण के लिए मुसलमान निरीक्षक की नियुक्ति की जाए।

## स्त्री शिक्षा

1. बालिका विद्यालयों की अधिक आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए।

2. बालिकाओं का पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तक बालकों से भिन्न है।

3. निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था।

4. बालिकाओं को छात्रवृत्तियाँ देने की व्यवस्था, छात्रावास की व्यवस्था।

## गुण

1. आयोग ने शिक्षा की स्पष्ट नीति की घोषणा की।

2. नार्मल स्कूलों की स्थापना

3. जनसाधारण की शिक्षा को शिक्षा का प्रमुख अंग स्वीकार करके प्रसार एवं सुधार के लिए सरकार को सुझाव दिया जिससे जनसाधारण की शिक्षा का विकास हुआ।

4. ~~नार्मल स्कूलों की स्थापना~~

4. मुस्लिम शिक्षा के लिए व्यापक सु

5. स्त्री शिक्षा को निःशुल्क बनाने का प्रयास।

13 AUGUST TUESDAY 2019

225-140 WEEK 33

## दोष

1. आयोग ने प्राथमिक शिक्षा का दायित्व स्थानीय निकायों पर सौंप कर, प्रान्तीय सरकारों को अपने कर्त्तव्यों से विमुख कर दिया।

2. माध्यमिक शिक्षा व्यक्तिगत प्रयासों पर छोड़ दिया।

3. आयोग ने राजकीय विद्यालयों में धार्मिक नीति अपनाकर, धार्मिक शिक्षा देने को रोक देने से देश की आध्यात्मिकता को आघात लगा था।